



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 859 राँची, बुधवार,

30 अक्टूबर, 2019 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2019

एस० ओ०-80--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Suo Moto Writ Petition (Criminal) No.-1/2019** में दिनांक-25.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार **Scheme on Fast Track Special Courts (FTSCs) for Expeditious Disposal of Cases of Rape and Protection of Children Against Sexual Offences (POCSO) Act** के अनुरूप राज्य सरकार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से **Rape** एवं **POCSO Act** के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन हेतु झारखण्ड राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 22 (बाईस) फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का अस्थाई रूप से एक वर्ष हेतु, जो वर्ष (2019-2020) एवं (2020-2021) में सन्निहित होगा, गठन करती है। इनमें से 08 विशेष न्यायालय केवल **POCSO Act** से संबंधित वादों का विचारण करेंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल रूप से प्रभावी होगी।

(बी01/विधि-कोर्ट-गठन-280/2013-2055/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2019

एस०ओ०-80-- निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(बी01/विधि-कोर्ट-गठन-280/2013-**2055**/जे0)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

NOTIFICATION 30th October, 2019

S.O.80-In compliance of the order dated-25.07.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court in **Suo Moto Writ Petition (Criminal) No.-1/2019**, the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, is pleased to constitute 22 (Twenty Two) Fast Track Special Courts of the rank of District and Additional Sessions Judge for trial and disposal of pending cases of Rape and POCSO Act temporarily for one year, spread over year (2019-2020) & (2020-2021) in consonance with **the Scheme on Fast Track Special Courts (FTSCs) for Expeditious Disposal of Cases of Rape and Protection of Children Against Sexual Offences (POCSO) Act** formulated by the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, New Delhi.

2. This Notification will come into force with immediate effect.

(File No.-B1/vidhi-Court-Gathan-280/2013-**2055**/J)

By the order of Governor of Jharkhand

(Pradeep Kumar Srivastava)

Principal Secretary-cum-L.R.

Law Department, Government of Jharkhand.
